

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 1049/2012/जोधपुर

मैसर्स कानूनगो एलांयज प्रा.लि.
बासनी, जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत्त-सी, जोधपुर

प्रत्यर्थी

अपील संख्या 1706/2012/जोधपुर

वाणिज्यिक कर अधिकारी
वृत्त-सी, जोधपुर

अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स कानूनगो एलांयज प्रा.लि.
बासनी, जोधपुर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री आर.आर.सिघवी
अभिभाषक
श्री जमील जई
राजकीय उप अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 18.08.2015

निर्णय

उपरोक्त दोनों अपीलों में से अपील संख्या 1049/2012/जोधपुर व्यवहारी की ओर से एवं अपील संख्या 1706/2012/जोधपुर वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-सी, जोधपुर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) की ओर से अपीलीय प्राधिकारी, जोधपुर-प्रथम, वाणिज्यिक कर जोधपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा गया है) के द्वारा अपील संख्या 42/आरवैट/जेयूसी/11-12 में पारित किये गये आदेश दिनांक 05.03.2012 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। चूँकि दोनों अपीलें अपीलीय अधिकारी के एक ही आदेश के विरुद्ध हैं तथा दोनों अपीलों में समान बिन्दु निहित होने के कारण इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक-पृथक पत्रावलियों पर रखी जा रही हैं।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2007-08 का मूल कर निर्धारण आदेश दिनांक 09.03.2010 को पारित किया गया। आलौच्य अवधि में अपीलार्थी द्वारा रूपये 12,13,880/- की प्रयुक्त कार (Used car) तथा रूपये 5,00,000/- का प्लान्ट एवं मशीनरी का विक्रय किया गया, जिस पर कर निर्धारण होने से रह जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 26 एवं 55 के तहत पुनः कर निर्धारण आदेश दिनांक 02.11.2011 को पारित करते हुए 4 प्रतिशत की दर से कर रूपये 68,555/-, ब्याज रूपये 24,680/- एवं अधिनियम की धारा 61(1) के अन्तर्गत शास्ति रु. 1,37,110/- का आरोपण किया

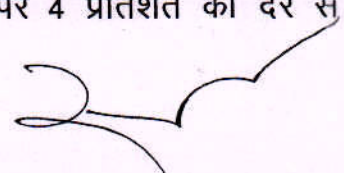
2

गया। अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उक्त आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी अपील अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 05.03.2012 से आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए प्लान्ट एवं मशीनरी के विक्रय पर किये गये करारोपण एवं शास्ति को अपास्त करते हुए प्रयुक्त कार के विक्रय पर आरोपित कर एवं ब्याज को यथावत रखते हुए उस पर आरोपित शास्ति को अपास्त किया गया है। अतः प्रयुक्त कार के करारोपण एवं ब्याज के सम्बन्ध में अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्लान्ट एवं मशीनरी पर आरोपित किये गये कर, ब्याज एवं शास्ति तथा प्रयुक्त कार पर आरोपित शास्ति को अपीलीय अधिकारी द्वारा अपास्त किये जाने को राजस्व की ओर से विवादित किया गया है।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी ने बहस के दौरान कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रकरण धारा 26 के तहत खोलना त्रुटिपूर्ण है। अपीलीय अधिकारी द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के प्रावधानों में करारोपण के सिद्धान्तों व वेट अधिनियम के प्रावधानों में अन्तर मानने को त्रुटिपूर्ण बताया। अपीलीय अधिकारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के निर्णय एसोसियेटेड्स स्टोन बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी (2003) 2 आर.टी.आर. 245 को लागू होना नहीं मानने को उच्चतर न्यायालयों की अवमानना करने का कथन किया। पुरानी प्रयुक्त कार का विक्रय नियमित व्यापार के क्रम में आनुषंगिक/प्रासंगिक नहीं है। उक्त कथन के साथ विद्वान अभिभाषक ने अपील संख्या 1049/12/जोधपुर स्वीकार किये जाने की प्रार्थना करते हुए राजस्व की ओर से अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलीय आदेश में यथावत रखे गये कर एवं ब्याज को यथावत रखने जाने का समर्थन करते हुए कथन किया कि प्रयुक्त कार के विक्रय पर करारोपण छूट जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वेट अधिनियम की धारा 26 के तहत प्रकरण में पुनः कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति आरोपित किये जाने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की गयी है तथा अपीलीय अधिकारी ने भी इस सीमा तक कर निर्धारण आदेश की पुष्टि किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने अपीलार्थी व्यवहारी की अपील अस्वीकार कर राजस्व की ओर से प्रस्तुत अपील संख्या 1706/12/जोधपुर स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। कर निर्धारण आदेश से स्पष्ट है कि कर निर्धारण अधिकारी ने पुरानी कार स्थायी सम्पत्तियों के विक्रय पर कर निर्धारण छूट जाने के कारण वेट अधिनियम की अनुसूची IV के क्रम संख्या 144 use motor vehicle पर 4 प्रतिशत की दर से कर निर्धारित किया।



इस सम्बन्ध में वेट अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन किया जाना समीचीन होगा :-

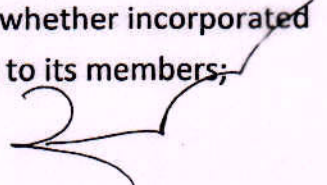
Sec. 2. Definitions.-

(6) "business" includes-

- (i) any trade, commerce or manufacture; or
- (ii) any adventure or concern in the nature of trade, commerce or manufacture - whether or not such trade, commerce, manufacture, adventure or concern is carried on with a motive to make gain or profit, and whether or not any gain or profit accrues from such trade, commerce, manufacture, adventure or concern; or
- (iii) any transaction in connection with or incidental or ancillary to such trade, commerce, manufacture, adventure or concern; or
- (iv) any transaction in connection with or incidental or ancillary or consequential to the commencement or closure of such business; or
- (v) any occasional transaction in the nature of such trade, commerce, manufacture, adventure or concern whether or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction;

(11) "dealer" means any person, who carries on business in any capacity, of buying, selling, supplying or distributing goods directly or otherwise, or making purchases or sales as defined in clause (35) for himself or others, whether for cash or deferred payment, or for commission, remuneration or other valuable consideration and shall include-

- (i) a factor, broker, commission agent, *del credere* agent or any other mercantile agent, by whatever name called, and whether of the same description as hereinbefore mentioned or not, who carries on the business of buying, selling, supplying or distributing any goods belonging to any principal whether disclosed or not;
- (ii) an auctioneer, who sells or auctions goods belonging to any principal, whether disclosed or not and whether the offer of the intending purchaser is accepted by him or by the principal or a nominee of the principal;
- (iii) a manager or an agent, of a non-resident dealer who buys, sells, supplies or distributes goods in the State belonging to such dealer;
- (iv) any society, club, trust or other association, whether incorporated or not, which buys goods from or sells goods to its members;



- (v) casual trader;
- (vi) the Central or any State Government or any of their Departments or offices which, whether or not in the course of business, buy, sell, supply or distribute goods directly or otherwise, whether for cash or deferred payment or for commission, remuneration or other valuable consideration; and
- (vii) any trading, commercial or financial establishment including a bank, an insurance company, a transport company and the like which, whether or not in the course of its business, buys, sells, supplies or distributes goods, directly or otherwise, whether for cash or deferred payment, commission, remuneration or other valuable consideration;

Explanation – A person, who sells agricultural or horticultural produce, grown by himself or grown on any land in which he has an interest as owner or tenant as defined in the Rajasthan Tenancy Act, 1955 (Act No. 3 of 1955), shall not be deemed to be a dealer in respect of such sales within the meaning of this clause;

- (40) “taxable turnover” means, that part of turnover, as may be determined after making such deductions from the total turnover as may be prescribed on which a dealer shall be liable to pay tax under this Act ;
- (41) “turnover” means the aggregate amount of sale price received or receivable by a dealer including purchase price of the goods which are subject to tax under sub-section (2) of section 4 “but shall exclude the sale price or part of sale price, if any, in respect of sales of goods which were purchased in the State by the dealer upon payment of tax on the maximum retail price of such goods or, where tax on maximum retail price of such goods were paid in the State on an earlier occasion;

4. Levy of tax and its rate. –

- (2) Every dealer who in the course of his business purchases any good other than exempted goods in the circumstances in which no tax under sub-section (1) is payable on the sale price of such goods and the goods are disposed off for the purpose other than those specified in clause (a) to (g) of sub-section (1) of section 18, shall be liable to pay tax on the purchase price of such goods at the rate mentioned against each of such goods in Schedule-III to Schedule VI of the Act.

इसी प्रकार विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उद्धरित न्यायिक दृष्टान्त (2003) 2 आर.टी.आर. 245 एसोसियेट्स स्टोन बनाम



वाणिज्यिक कर अधिकारी में माननीय बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त 99 एस.टी.सी. 117 का अवलम्ब लेते हुए निम्न निर्णय पारित किया है :-

"8. As regards the second point whether the sale of old and used vehicles/bodies purchased earlier u/s 5CCCC of the RST Act after paying full tax could again be taxed under the law, I feel inclined to agree with the contention of the learned counsel for the appellants/assessee when he contended that the sale of these old vehicles having no connection with their main business of manufacture and sale of Kota Stones could not be taken as "sale" within the meaning of section 2(38) of the RST Act and hence these transactions of sale of old and discarded vehicles could not be taxed under the law. The fact that all these vehicles/bodies were purchased u/s 5CCCC of the RST Act after paying full tax precluded the learned AA from levying tax, interest and penalty on its sales again. the rulings relied upon by the learned counsel in this regard fully help their case. **In this view of the matter, impugned order levying tax, interest and penalty of the sale of the old and used vehicles/bodies only deserved to have been quashed and set aside being contrary to law.** Learned DC (Appeals), therefore, seems to have committed an error while remanding the case back to the learned AA for further inquiry without considering the argument made before him to this effect. In view of this discussion, the second point is answered in the negative."

इसी प्रकार माननीय राजस्थान कर बोर्ड के न्यायिक दृष्टान्त (2013) 36 टैक्स अपडेट 173 वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त, अजमेर बनाम मैसर्स गुरुकृपा एजेंसीज, ब्यावर में निम्न निर्णय पारित किया गया है :-

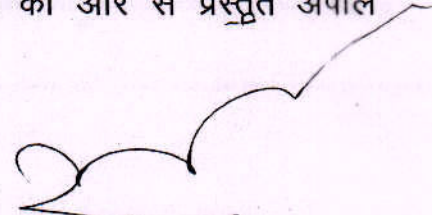
"6. I have carefully gone through the arguments of both the learned counsels and have also looked into the facts of the record. As regarding the sale of old and used vehicle, it is crystal clear that the car which has been sold by the Respondent is registered in the name of Mrs. Rajinder Kaur, who is the sole proprietor of the firm. I inclined to agree with the contention of the learned counsel that the sale of this old vehicle having no connection with her main business, could not be taken as "sale" within the meaning of section 2(35) of the Act and hence this transaction of sale of old vehicle cannot be taxed under the Act. The rulings relied upon by the learned counsel in this regard fully help her case. I have gone through the decision of the Hon'ble RTB relied upon by the learned Appellate Authority while setting aside the order of penalty in this case. This decision fully covers the facts of this case and, therefore, in this view, learned Appellate Authrotiy did not commit any error while passing the impugned

order. Thus I find nothing wrong in the order passed by the learned appellate authority and therefore, no interference is required."

माननीय राजस्थान कर बोर्ड के उपरोक्त न्यायिक दृष्टान्तों में प्रतिपादित सिद्धान्त से यह पीठ पूर्णतः सहमत है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रयुक्त वाहन की बिक्री पर करारोपण की कार्यवाही किये जाने में एवं अपीलीय अधिकारी द्वारा उक्त करारोपण की पुष्टि किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। रिकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी द्वारा किसी भी तरह का संव्यवहार छुपाया गया नहीं है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय कृष्ण इलेक्ट्रिकल में प्रतिपादित सिद्धान्त के आलोक में अपीलीय अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 61 (1) के आरोपित शास्ति अपास्त किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपील स्वीकार की जाकर कर निर्धारण अधिकारी का आदेश दिनांक 02.11.2011 एवं अपीलीय अधिकारी का आदेश दिनांक 05.03.2012 अपास्त किये जाकर कर निर्धारण अधिकारी की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।


(सुनील शर्मा)
सदस्य